नईदुनिया

बांग्लादेश में 300 से अधिक भारतीय ट्रक फंसे, मंदिरों पर हमला

ढाका। बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंसा भड़कने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर 250-300 भारतीय ट्रक फंसे हुए हैं। वहीं हिंसक भीड़ ने ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और चार हिंदू मंदिरों पर हमला किया है। इन हमलों में मंदिरों को मामूली नुकसान हुआ है। कुछ हिंदुओं को भी निशाना बनाए जाने की सूचना है।

ट्रकों की आवाजाही रूकने पर पेट्रापोल के क्लीयरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने बताया कि पेट्रापोल लैंड पोर्ट से माल की आवाजाही सोमवार को रुकने से ट्रकों की आवाजाही बंद हो गई है।

बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देबनाथ ने बताया है कि देश के चार मंदिरों पर हमले हुए हैं। इन हमलों में मंदिरों को मामूली नुकसान हुआ है।

प्रधानमंत्री हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में स्थिति को लेकर डर है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। भीड़ द्वारा निशाना बनाए गए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन मार्च 2010 में हुआ था। इस केंद्र में योग, हिंदी, भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय नृत्य कलाओं के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस केंद्र के पुस्तकालय में भारत से संबंधित 21 हजार पुस्तकों का भी संग्रह है।

बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर भारत-बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल लैंड पोर्ट से माल की आवाजाही सोमवार को रुक गई। पेट्रापोल के क्लीयरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने बताया कि बांग्लादेश की ओर 250-300 भारतीय ट्रक फंसे हुए हैं।

पेट्रापोल भारत-बांग्लादेश की सीमा पर स्थित लैंड पोर्ट है। चक्रवर्ती ने कहा कि हम बांग्लादेश के नए प्रशासन से ट्रकों, माल और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे। बता दें कि हर दिन औसतन 450-500 ट्रक भारत से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल के माध्यम से बांग्लादेश जाते हैं। लगभग 150-200 ट्रक दूसरी तरफ से आते हैं।

सालाना, लगभग 22 लाख लोग पेट्रापोल चेक प्वाइंट के माध्यम से सीमा पार करते हैं। पेट्रापोल बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। यह कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं, एलआईसी ने सोमवार को कहा कि एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का कार्यालय सात अगस्त तक बंद रहेगा।

न्यूज ब्रीफ

सिएटल में गोलीबारी की घटना में चार लोग घायल

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब राज्य वॉशिंगटन के सिएटल में गोलीबारी में कम से कम चार लोग घायल हो गए। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को घटनास्थल पर 20 साल की एक लड़की मिली, जिसके सिर पर गोली लगने का घाव था और 20 साल का एक लड़का मिला, जिसकी उंगली में गोली मारी गई थी। जब पुलिस इस घटना की जांच कर रही थी, तब उन्हें शख्स के सिर और उसके पीठ के निचले हिस्से पर गोली के घाव दिखे और उनके एंकल से एक गाड़ी स्वीडिश फर्स्ट हिल अस्पताल के एंट्री गेट से टकरा गई। पुलिस ने जांच में पाया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन पर कई बार गोलियां चलाई गई थीं। पुलिस के अनुसार इसके अतिरिक्त 20 साल का एक तीसरा व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगने के घाव के साथ पास के कैसर परमानेंट मेडिकल केंद्र में चला गया। पुलिस ने कहा कि गोलीबारी के लिए जिम्मेदार संदिग्ध आरोपी भाग गया और इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामले की जांच की जा रही है। हाल ही में इससे पहले न्यूयॉर्क के रोचेस्टर शहर के एक पार्क में गोलीबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। साथ ही घटना में छह लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल पर मौजूद लोगों से इस घटना का वीडियो भी मांगा।

चीन से गदगद पाक बोला-जो उसने किया है वो अमेरिका भी नहीं कर सकता

लाहौर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन यह पाक और चीन के बीच संबंधों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। लाहौर के मॉडल टाउन स्थित आवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन यह पाक और चीन के बीच संबंधों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने देश के लिए जो किया है, वह अमेरिका कभी नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञ पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। चीनी विशेषज्ञों ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने चीन से फिर से कर्ज का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, अगर चीन द्वारा पाकिस्तान सरकार को कर्ज चुकाने के लिए पांच से सात वर्ष का समय दिया गया तो देश में बिजली के दामों के साथ-साथ महंगाई को कम किया जा सकेगा। इस दौरान, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने देश में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई। कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भी कहा था कि बेहतर संबंधों के लिए चीन के साथ रिश्तों की कुर्बानी नहीं दे सकते। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने कहा, हमारे लिए अमेरिका के साथ रिश्ते और चीन के साथ रिश्ते, दोनों ही जरूरी हैं। उन्होंने कहा, हम इस बात में यकीन नहीं रखते कि एक देश के साथ संबंधों के लिए दूसरे देश के साथ रिश्तों की कुर्बानी दे दी जाए।

ब्रिटेन सरकार की मांग, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में हो बांग्लादेश हिंसा की जांच

लंदन। बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब ब्रिटेन सरकार ने इसकी स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच की मांग की है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। बांग्लादेश अब अंतरिम सरकार का इंतजार कर रहा है और सेना प्रमुख प्रदर्शनकारियों से मिलने की योजना बना रहे हैं, जिससे लगता है हिंसक विद्रोह के बाद बांग्लादेश में अब स्थिति सामान्य हो सकती है। इस आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जो 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली के साथ शुरू हुआ था, जिसमें युवा बेरोजगारी ज्यादा थी। जैसे-जैसे अशांति बढ़ती गई, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हमला बोल दिया उनके आवास परिसर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और सैन्य हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भारत आ गईं। शेख हसीना ने भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। लंदन जाने की योजना है लेकिन लंदन प्रशासन की ओर से उन्हें शरण देने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि ब्रिटेन बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य तय करने के लिए कार्रवाई देखना चाहता है, लेकिन उन्होंने शेख हसीना के आगमन का उल्लेख नहीं किया है। लैमी ने कहा बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंसा और जान-माल की हानि हुई है। सेना प्रमुख द्वारा एक संक्रमणकालीन अवधि की घोषणा की गई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की संसद को किया संबोधित, बोलीं

भारत और फिजी में जीवंत लोकतंत्र सहित काफी कुछ एक समान है

सुवा। फिजी की दो दिवसीय यात्रा पर गईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को वहां की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से उभर रहा है। भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनने के साथ-साथ प्राथमिकताओं के अनुसार फिजी के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस मौके पर दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए अपनी साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक साथ आने को कहा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आकार में बहुत अंतर होने के बावजूद भारत और फिजी में जीवंत लोकतंत्र सहित काफी कुछ एक समान है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले इसी हॉल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ मूल्यों का जिक्र किया था जो भारत और फिजी को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र, हमारे समाज की विविधता तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बताता है। ये साझा मूल्य शाश्वत हैं, आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि बाकी दुनिया को फिजी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिजी की सौम्य जीवनशैली, परंपराओं तथा रीति-रिवाजों के प्रति गहरा सम्मान, खुला और बहुसांस्कृतिक वातावरण, फिजी को तेजी से संघर्षों में घिर रही इस दुनिया में इतना खास बनाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फिजी वह जगह है जहां बाकी दुनिया अपनी खुशियां ढूंढने आती है।

राष्ट्रपति मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी की राजधानी सुवा में हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी में अपने संबोधन में कहा कि भारत एक सक्षम और संवेदनशील देश के रूप में उभर रहा है। हमने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाई है। पिछले वर्ष हमारी जी-20 अध्यक्षता की ऐतिहासिक सफलता ने दर्शाया कि भारत का समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुखी नेतृत्व विश्व के लिए क्या कर सकता है। जैसा कि हमने जी-20 की अध्यक्षता के दौरान किया था। हम ग्लोबल साउथ के हितों को जोर से आवाज देने के लिए हर वैश्विक मंच का उपयोग करना जारी रखेंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और सुरक्षित दुनिया बनाने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या ओसीआई कार्ड सहित अनेक पहलें शुरू की हैं। प्रवासी परिवारों की युवा पीढ़ी के लिए हमारे पास उन्हें अपनी भारतीय जड़ों से जोड़ने के लिए एक भारत को जानो कार्यक्रम है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में फिजी के युवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सुवा में स्थापित होने वाले 'सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल' सहित नयी परियोजनाएं फिजी और व्यापक प्रशांत क्षेत्र के लोगों की प्राथमिकता वाली जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू का 'स्टेट हाउस' में राष्ट्रपति कटोनिवेरे ने स्वागत किया जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

उन्होंने सुवा में महात्मा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां उपस्थित छात्रों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने सुवा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रपति फिजी में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत

सुवा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी की राजधानी सुवा में हैं। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मित्रता के गहरे संबंधों का परिचायक है। यह सचित्र विवरण भारत की राष्ट्रपति के एक्स हैंडल पर साझा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू का सुवा पहुंचने पर फिजी के प्रधानमंत्री सीटिवेनी राबुका ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति फिजी के बाद न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर-लेस्ते की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने पिछले दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रपति की यात्रा का ब्यौरा साझा किया था। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पांच से 10 अगस्त तक तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर भारत ने विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। यह तीनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आते है। भारत और फिजी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं।

चीन को समर्पित हो सकती है बांग्लादेश की नई सरकार

ढाका। पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, वहां राजनीतिक अस्थिरता होना अच्छा नहीं है। इससे राजनयिक ही नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्ते और नागरिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी 4096 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। इसी प्रकार यदि राजनयिक संबंधों की बात करें तो भारत पहला देश था, जिसने उसके अस्तित्व में आने के बाद 1971 में राजयनिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश में बगावत भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा दो कारणों से है। एक इससे भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध कुछ हद तक प्रभावित होंगे। दूसरे वहां बनने वाली नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सेना की अंतरिम सरकार से भी वैसे संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती है जैसे शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार से थी।

भविष्य में अगर वहां शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी सरकार नहीं बनाती है और कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाती है तो यह आशंका है कि उसका झुकाव चीन की तरफ हो सकता है। तीसरी, आशंका यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता बढ़ सकती है, जिन्हें शेख हसीना के शासन में काफी हद तक नियंत्रण में रखा गया था। उन्हें नियंत्रित करना बांग्लादेश सरकार का जिम्मा होगा, लेकिन परोक्ष रूप से वह भारतीय जनमानस को थोड़ा-बहुत प्रभावित कर सकते हैं।जहां तक शेख हसीना के भारत के रास्ते लंदन रवाना होने की बात है, इस बात से बांग्लादेश के साथ संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। भारत ने उन्हें यहां रहने की अनुमति नहीं देकर सिर्फ उतना ही किया जितना एक राजयनिक प्रोटोकॉल के तहत किया जा सकता था। इसलिए बांग्लादेश की नई सरकार के रुख पर इसका कोई असर नहीं होगा।

हालांकि पिछले पांच दशकों में बांग्लादेश की राजनीति में उतार-चढ़ाव आए और फौजी राष्ट्रपति के हाथ में भी कमान रही, लेकिन भारत-बांग्लादेश संबंधों में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिखा। इसलिए इस घटना को भी विशेषज्ञ अच्छा तो नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत निराश नहीं हैं।रक्षा विशेषज्ञों की का कहना है कि कहा कि शेख हसीना भारत समर्थक और लंबे समय से सत्ता में थी। इससे पूर्व भी जब 2001 तक वह सत्ता में थी तो भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ हुए थे। फिलहाल वहां सेना सत्ता संभालने जा रही है, जिसका रुख भारत को लेकर तटस्थ रहने की संभावना है।

कमला हैरिस को सोशल मीडिया पर 4 हजार बार धमकी देने वाले पर चलेगा मुकदमा

वाशिंगटन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से एक युवक इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक दो बार नहीं बल्कि हजारों पर उन्हे जान से मारने की धमकी दे डाली। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रैंक लुसियो कैरिलो ने कमला हैरिस, राष्ट्रपति जो बाइडन, एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे सहित एरिजोना राज्य के कई अधिकारियों और अन्य लोगों को दक्षिणपंथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेटर पर कई धमकियां दी थीं। एफबीआई ने कैरिलो की 4,359 पोस्ट पाईं, जिनमें कमला हैरिस सहित दूसरे कई सराकरी अधिकारियों को निशाना बनाया गया था।

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी कई पोस्ट में कैरिलो ने कथित तौर पर हैरिस की आंखें निकालने की धमकी दी और उपराष्ट्रपति को मारने के विभिन्न तरीकों को विस्तार से सामने रखा। कैरिलो ने कथित तौर पर एक अपशब्द भरे भाषण में लिखा कि 'मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। उसने उम्मीद जताई कि कमला हैरिस धीमी पीड़ादायक मौत मरेगी। अदालत के रिकॉर्ड में कई ऐसे ही पोस्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी और साफ धमकियां दी गई हैं। जिसमें 2023 में एक इस्लामोफोबिक पोस्ट भी शामिल है। जिसमें उसने लिखा था कि लोगों को अपनी बंदूकें लेकर बाहर जाना चाहिए और सभी मुसलमानों को मार देना चाहिए। जब एफबीआई एजेंट पहली बार सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में कैरिलो के घर पहुंचे, तो कैरिलो ने कहा कि 'मैंने इसे पोस्ट किया है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार कैरिलो ने यह भी कहा कि 'मुझे लगता है कि मुझे एक वकील की जरूरत पड़ेगी। संघीय एजेंटों ने उनके घर से दो हथियार बरामद किए, जिसमें 2023 में खरीदी गई एक पिस्तौल और इस साल खरीदी गई एक राइफल शामिल है।

पाकिस्तान में इस साल आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान 139 सैनिक मारे गए

पाकिस्तानी सेना ने पिछले 15 दिनों के दौरान 24 आतंकवादियों को मार गिराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि 2024 के पहले सात महीनों के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ जारी लड़ाई में अधिकारियों सहित 139 सैनिकों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। जिसमें सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के व्यापक आतंकवाद विरोधी प्रयासों और पेशेवर गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और एलईए ने देश भर में 23,622 खुफिया-आधारित ऑपरेशन किए। कुल मिलाकर 2,045 ऑपरेशन अकेले पिछले 15 दिनों में किए गए।

शरीफ ने पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसियों, पुलिस और अन्य एलईए के अथक प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान 24 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अधिकारी ने कहा कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को फितना अल-खवारिज (बाहरी विद्रोह) और सभी संबंधित आतंकवादियों को खारिजी (बहिष्कृत) करार दिया है। महानिदेशक ने कहा कि यह शरारत करने वाला समूह है। यह न तो कोई विचारधारा है और न ही इसका धर्म या पाकिस्तान से कोई लेना-देना है। अधिकारी ने कहा कि पूरा देश बहादुर शहीदों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देता है। यह प्रतिबद्धता देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, एलईए और खुफिया एजेंसियों के अटूट फोकस को रेखांकित करती है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ तब तक लड़ाई जारी रखने के देश के संकल्प की पुष्टि की जब तक कि अंतिम आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता, जिससे पाकिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जारी किया आदेश

बांग्लादेश की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को तत्काल रिहा किया जाए

ढाका। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट होने और देश छोड़ने के बाद जहां सेना ने सत्ता संभाल ली है। वहीं देशभर में अराजकता और हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, बैठक में सर्वसम्मति से बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को रिहा करने का फैसला किया गया। इसके अलावा, छात्र भेदभाव विरोधी आंदोलन और हाल की घटनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किए गए सभी बंदियों को रिहा करने का फैसला किया गया। सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी तरह से बाधित न होने देने के लिए भी मजबूत सहमति बनी।

राष्ट्रपति की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीन, थल सेनाध्यक्ष, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक की अध्यक्षता में बंगभवन में एक बैठक आयोजित की गई। देश के समाज प्रतिनिधि बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में शोक प्रस्ताव लिया गया और उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति और क्षमा के लिए प्रार्थना की गई। बैठक में तुरंत अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया गया। बैठक में सभी से देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और

सहनशीलता बरतने का आग्रह किया गया और सेना को लूटपाट और हिंसक गतिविधियों से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सर्वसम्मति से बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, भेदभाव विरोधी आंदोलन और हाल ही में विभिन्न मामलों में हिरासत में लिए गए सभी कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि समुदाय को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

इससे पहले बांग्लादेश में सोमवार को बवाल बढ़ने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भारत पहुंच गई हैं। ज्ञात रहे कि गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के सेफ हाउस में रखा गया है। इस समय बांग्लादेश के हालत अस्थिर बने हुए हैं। कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है।

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आज-कल में ही शुरू हुआ। पहले भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी इस कथित विवादास्पद रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करने की मांग कर थे, जिसके तहत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम (1971) में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस राजी

बांग्लादेश में लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहीं शेख हसीना के छात्र आरक्षण आंदोलन की हिंसक लपटों के बीच देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बांग्लादेश के प्रमुख बांग्लाभाषी अखबार प्रोथोम अलो के अनुसार, नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने को राजी हो गए हैं। प्रोथोम अलो और द डेली स्टार के अनुसार, आंदोलन के समन्वयकों में से एक नाहिद इस्लाम ने मंगलवार तड़के एक वीडियो संदेश में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उनकी प्रो. यूनुस से बात हो गई है। छात्रों के आह्वान पर वह बांग्लादेश की रक्षा के लिए यह अहम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए हैं।